आईटीआई बनेंगे एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर : वित्त मंत्री

केंद्र सरकार आईटीआई को एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में बदलेगी

अपग्रेडेशन के लिए 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल लागू किया जाएगा

नई दिल्ली, 18 सितंबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की है कि केंद्र सरकार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में बदलने की योजना बना रही है. यह पहल युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और तेजी से बदलते औद्योगिक माहौल के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से की गई है.

अपग्रेडेशन के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल- इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (आईएफक्यूएम) के वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले दो-तीन वर्षों से कौशल विकास और अपस्किलिंग पर ध्यान दे रही है और इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने बताया कि आईटीआई को आधुनिक बनाने के लिए एक हब-एंड-स्पोक मॉडल लॉन्च किया गया है. अगर राय इस मॉडल को अपनाते हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में अपग्रेड करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता देगी.

युवाओं को मिलेगी व्यावहारिक एआई ट्रेनिंग- सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एआई से संबंधित अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने के लिए आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे कुछ प्रमुख संस्थानों की पहचान की है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल छोड़ने वाले, पास होने वाले या डिग्री प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवा को एआई-आधारित कौशल सिखाया जाए. ये हब छात्रों को व्यावहारिक एआई प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

रोजगार के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपील

वित्त मंत्री ने युवाओं को उनकी शिक्षा पूरी होने के तुरंत बाद रोजगार के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हालांकि युवाओं के पास डिग्री है, लेकिन वे सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कंपनियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं. उन्होंने इस काम में सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र से भी भागीदारी करने की अपील की ताकि युवाओं को शीघ्र और सीधे रोजगार मिल सके.

क्रिटिकल मिनरल पर चीन का नियंत्रण चिंताजनक : आयोग

नई दिल्ली, 18 सितंबर. नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने गुरुवार को इंडिया माइनिंग समिट 2025 में क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति पर एक देश (चीन) के नियंत्रण को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह एकाधिकार दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है और प्रतिस्पर्धी आपूर्ति श्रृंखला बनाने की तत्काल आवश्यकता है.

विरमानी ने एक साक्षात्कार में बताया कि दुनिया भर में खनिज बिखरे हुए हैं, लेकिन धातुओं की 80 से 90 प्रतिशत आपूर्ति एक ही देश द्वारा नियंत्रित होती है. उन्होंने इसे एक तरह का देश-एकाधिकार बताया. यह तब और भी चिंताजनक हो गया जब चीन ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल के

निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जिससे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई. विरमानी ने कहा कि दुनिया के कई देश इस समस्या को लेकर चिंतित हैं. भारत भी अपनी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसे कदम उठा रहा है, जिसे 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था.

भारत की ग्रोथ स्टोरी बनी वैश्विक प्रेरणा : सीईए

कोलकाता, 18 सितंबर- भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को भारत की आर्थिक विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य देश इतने बड़े आकार और विविधता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर इतनी व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रगति का प्रयास नहीं कर रहा है.

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अपनी सभी चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम है.

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारत हमेशा से एक रोमांचक कहानी रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कम आय वाले देश से निम्न-मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि हमें अपनी असफलताओं के साथ-साथ अपनी सफलताओं से भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सफलताएं हमें अनिश्चितता के इस दौर में प्रेरणा और अनुस्मारक देती हैं कि हम अपनी चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं.

घरेलू और यूरोपीय मांग से दवा क्षेत्र को मजबूती

वित्त वर्ष 2026 में 7-9% राजस्व वृद्धि का अनुमान

अमेरिकी बाजार में सुस्ती, 3-5% वृद्धि की उम्मीद

नई दिल्ली, 18 सितंबर. भारतीय दवा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है. अमेरिकी बाजार में धीमी गति के बावजूद, मजबूत घरेलू और यूरोपीय मांग के दम पर वित्त वर्ष 2026 में 7-9% की राजस्व वृद्धि हासिल करने की संभावना है. यह जानकारी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों और नियामक अनिश्चितताओं के कारण भारतीय दवा उद्योग के सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वहां की राजस्व वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के 10% से घटकर 3-5% रह सकती है. हालांकि, इस गिरावट की भरपाई घरेलू और यूरोपीय बाजारों से होने की उम्मीद है, जहाँ क्रमशः 8-10% और 10-12% की वृद्धि का अनुमान है.

आईसीआरए की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनियों का परिचालन लाभ मार्जिन 24-25% पर स्थिर रहेगा. यह स्थिरता कच्चे माल की कीमतों में अनुकूलता, बेहतर परिचालन दक्षता और विशेष उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण संभव होगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियाँ अब सामान्य दवाओं के बजाय जटिल मॉलिक्यूल्स और विशेष उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं. इसी वजह से अनुसंधान और विकास पर खर्च राजस्व के 6-7% पर स्थिर रहने का अनुमान है.

सकारात्मक दृष्टिकोण

रेटिंग एजेंसी ने इस सेक्टर के लिए अपना दृष्टिकोण स्थिर बनाए रखा है, क्योंकि राजस्व और आय में वृद्धि के साथ-साथ कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत है, जिससे उनकी तरलता और परिचालन लाभ मार्जिन बेहतर स्थिति में है. चिकित्सा प्रतिनिधियों की बेहतर उत्पादकता और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क के विस्तार से भी घरेलू दवा बिक्री को बढ़ावा मिला है.

पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण पर की चर्चा

गोयल ने निवेश संबंधों के विस्तार पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा

द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सके

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा पर गये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वहां अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान के साथ निवेश पर भारत-यूएई उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की.

इस बैठक में दोनों पक्षों में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा की और समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश सबंध पर बातचीत की.

गोयल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को कहा कि इस बैठक में, जिसमें यूएई के विदेश व्यापार मंत्री, डॉ थानी बिन अहमद अल ज़ेयोऊदी भी शामिल हुये. उन्होंने बताया की बैठक में भारत-यूएई व्यापारक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की सफलता का और लाभ उठाने के उपायों पर चर्चा हुई, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सके. वाणिज्य मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्रों में, निवेश और सहयोग के नये क्षेत्रों पर चर्चा की है, संभावनाओं का पता लगाया है.

यूएई ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में मजबूत भागीदारी के साथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बना हुआ है। मई 2022 में सीईपीए लागू होने के बाद से, द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार लगभग दोगुना हो गया है – वित्त वर्ष 2021 में 43 .3 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2024 में 83 .7 बिलियन डॉलर तक – गैर-तेल क्षेत्रों की ओर मजबूत धक्का के साथ. यूएई के अध्यक्ष शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान, अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग के अध्यक्ष अहमद जसीम अल ज़ाबी और आईएचसी के प्रबंध निदेशक सैयद बसर शुएब सहित अन्य प्रमुख हितधारकों से मिलने की उम्मीद है।

ईसीटीए से भारतीय निर्यात को मिला बढ़ावा

ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी पर मिला तरजीही टैरिफ

2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 24 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

मुंबई, 18 सितंबर. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भारतीय निर्यात के लिए 86 प्रतिशत उपयोगिता दर के साथ एक सफल व्यापारिक मॉडल साबित हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास- जनरल, मुंबई में आर्थिक सलाहकार जो वुडली ने यह बात कही.

सीआईआई ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो नेशनल समिट में बोलते हुए, वुडली ने कहा कि ईसीटीए ने भारतीय व्यवसायों को ऑस्ट्रेलियाई निर्यात, जैसे लिथियम दुर्लभ पृथ्वी, पर तरजीही टैरिफ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है.

भारत की आर्थिक स्थिति और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन

वुडली ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि 2030 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. उन्होंने भारत की इस वृद्धि में ऑस्ट्रेलिया के विश्वास और इसमें अवसरों को रेखांकित किया. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज द्वारा जारी आर्थिक रोडमैप में स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, कृषि-व्यवसाय और पर्यटन को भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक गलियारे के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है.

इंस्टामार्ट की मेगा सेल शुक्रवार से

नयी दिल्ली, 18 सितंबर ऑनलाइन त्वरित डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट 19 सितंबर से मेगा सेल शुरू कर रहा है, जिसमें 50 हजार से अधिक उत्पादों पर 90 प्रतिशत तक छूट की घोषणा की गयी है. क्विक इंडिया मूवमेंट सेल के तहत स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच, पावरबैंक और ऑडियो डिवाइस जैसी कैटेगरी में बंपर ऑफर मिलेंगे. साथ ही बैंक ऑफर्स, गोल्डन आवर डील और वोट-फॉर-योर-डील फीचर्स के जरिये खरीदारों को और भी बचत तथा शानदार अनुभव प्राप्त होगा.

पूंजी बाजार भारत के बुनियादी विकास के लिए महत्वपूर्ण

नई दिल्ली, 18 सितंबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार को वित्तपोषित करने में पूंजी बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि देश के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूंजी बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए, पांडे ने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचा एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसके लिए धैर्यवान पूंजी की आवश्यकता होती है.

पांडे ने बताया कि बुनियादी ढांचा कंपनियां आईपीओ, राइट्स इश्यू और निजी प्लेसमेंट का तेजी से उपयोग कर रही हैं, जो अब सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग पांचवां हिस्सा है. पिछले एक दशक में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने 12-14% की वार्षिक वापसी दी है, जो निवेशकों के लिए क्षेत्र के स्थिर मूल्य को दर्शाता है.

समाचार विशेष

इस सीट पर महागठबंधन के 3 दावेदार

एनडीए में भी टिकट की खींचतान; लोजपा और वाम दल भी सक्रिय

बाराचट्टी (गया). जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक नजदीक आ रही है, गया जिले की बाराचट्टी सुरक्षित एससी सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है. चौक-चौराहों से लेकर पंचायतों की बैठकों तक एक ही चर्चा छाई हुई है इस बार किसे मिलेगा टिकट?

विधानसभा सीट
बाराचट्टी

दलों के भीतर जोड़तोड़ और दबाव की राजनीति चरम पर है, जबकि जनता उम्मीदवार से ज्यादा विकास और ईमानदारी पर निगाहें गड़ाए बैठी है. पिछले चुनाव में यह सीट महागठबंधन के हिस्से में आई थी. हालांकि तब की उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा. अब एक बार फिर पार्टी के भीतर टिकट को लेकर रस्साकशी चल रही है. सूत्रों की मानें तो यहां कम से कम तीन दावेदार सक्रिय हैं. इनमें एक पारिवारिक विरासत से जुड़े चेहरे हैं, जबकि अन्य वे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन में वर्षों से पसीना बहाया है. राजद खेमे में बहस इस बात पर है कि क्या वफादार कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी या फिर राजनीतिक परिवारों की परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा.

एनडीए में टिकट की खींचतान- यह सीट वर्तमान में एनडीए के एक घटक दल के पास है. मौजूदा विधायक दोबारा दावेदारी कर रही हैं. लेकिन भाजपा और जदयू के स्थानीय नेता भी इस सीट को लेकर सक्रिय हैं. एनडीए खेमे से करीब तीन चेहरे टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ ने पटना से लेकर दिल्ली तक संपर्क साधकर दबाव बनाने की कोशिश तेज कर दी है.

माले और जनसुराज की सक्रियता

महागठबंधन के भीतर वामपंथी दल माले भी इस सीट पर दावेदारी जाता रहा है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की ओर से एक नया चेहरा सामने है, जिसे वैचारिक राजनीति और छात्र आंदोलन से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है. वहीं, जनसुराज पार्टी ने भी इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. इस दल से तीन नाम टिकट की दौड़ में हैं, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं. गांव-गांव जाकर वे लोगों के सुख-दुख में शामिल होने और एक नए विकल्प के रूप में सामने आने की कोशिश कर रहे हैं. हलांकि, दल टिकट के लिए जोड़तोड़ में लगे हैं.

अब झारखंड में कांग्रेस का बाउंस बैक प्लान

शुरू किया जमीनी स्तर से संगठन मजबूत करने का मिशन

रांची. झारखंड कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने का काम जमीनी स्तर से शुरू कर दिया है. पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायतों और प्रखंडों में जाकर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं. इसके तहत पार्टी नेता लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं.

इन बैठकों में जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं और कांग्रेस की नीतियों को समझाया जा रहा है. इस तरह कांग्रेस पूरे राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है ताकि हर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके. बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू लगातार प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं. हाल ही में सात दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजू ने संगठन सृजन अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. दरअसल, कांग्रेस पूरे देश में संगठन विस्तार पर जोर दे रही है. आलाकमान का निर्देश है कि हर पंचायत में पार्टी मजबूत हो, ताकि दिल्ली की बातें जनता तक पहुंचें और नेता-जनता के बीच संवाद स्पष्ट हो.

प्रदेश अध्यक्ष का राज्य दौरा- झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि वे सिर्फ एक प्रमंडल तक सीमित नहीं रह रहे, बल्कि पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं. उनका लक्ष्य राज्य के हर हिस्से में संगठन को मजबूत करना है. वे लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं.

बिना राज्य कमेटी के कांग्रेस का टिकट बंटवारा

पटना. घोड़े के आगे बग्घी लगाना एक मुहावरा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे असल में करके दिखाया है. कांग्रेस पार्टी ने बिहार में सीट बंटवारे की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी यानी छंटनी समिति की बैठक कर ली है.

कांग्रेस ने अजय माकन को इस छंटनी समिति का अध्यक्ष बनाया था. वे पिछले महीने 13 अगस्त को पटना पहुंचे थे और कांग्रेस की टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू किया था. स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक पिछले हफ्ते होने वाली थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है. वह बैठक दिल्ली में होने वाली थी. सोचें, स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू नहीं हुई थी. तभी कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को भीड़ लाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक कर ली और अब दूसरी बैठक नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन कौन सी सीटें मिलेंगी. कांग्रेस की बिहार में दुर्दशा यह है कि पार्टी के पास पिछले करीब सात साल से राज्य की कमेटी नहीं है.

विशेष इशारों-इशारों में मिल गई टाइमिंग, क्या बढ़ेगी कांग्रेस में बेचैनी?

पप्पू यादव की पीएम मोदी से सीक्रेट बात

पूर्णिया. पीएम मोदी सोमवार को पूर्णिया की धरती पर थे. पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए भवन और कमर्शियल विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही बिहार को 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात भी दी.

पीएम मोदी मंच पर सभी नेताओं से गर्मजोशी से मिले. लेकिन जिस अंदाज में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव से मिले, वह वीडियो देखने लायक था. पीएम मोदी और पप्पू यादव की मंच पर यह पहली मुलाकात थी. अगले ही मिनट में जब पीएम मोदी को मखाना की माला पहनाने का अनाउंसमेंट हुआ तो पप्पू यादव एक बार फिर से पीएम मोदी के पीछे आकर खड़े हो गए. पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद होने के नाते मंच पर उनकी उपस्थिति बनती ही है और यह प्रोटोकॉल भी है. लेकिन जिस अंदाज में वह पीएम मोदी से मिले, उससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी हो सकती है.

बिहार की राजनीति में वैसे तो अक्सर बड़े-बड़े मुद्दे सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे पर एक छोटे से वीडियो ने पूरे सियासी खेमे में चर्चा का विषय बन गया है. मामला है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पीएम मोदी की मंच पर हुई मुलाकात का. वीडियो देखकर लग रहा था कि पप्पू यादव पीएम से मिलने के लिए इतने बेचैन थे कि वह बार-बार उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे. वैसे, सांसद होने के नाते मंच पर उनकी जगह तो बनती ही है, लेकिन जिस अंदाज में वह पीएम मोदी से मिले, उसने कांग्रेस के कई नेताओं के पेट में जरूर मरोड़ पैदा कर दी होगी.

क्या इशारों-इशारों में हो गई कोई बात?

दरअसल, पीएम मोदी जब मंच पर आए तो उन्होंने सभी नेताओं से गर्मजोशी से हाथ मिलाया. लेकिन पप्पू यादव ने जिस अंदाज में पीएम के पीछे आकर उनको नमस्कार किया और पीएम ने भी उनका हालचाल जरूर पूछा होगा. शायद पप्पू यादव के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वह पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे थे. शायद यह पूर्णिया के विकास के संबंधित हो सकता है या फिर राजनीतिक भी. लेकिन पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज से लगा कि उन्होंने पप्पू यादव को आश्वस्त कर दिया. दोनों का यह वीडियो देखने लायक था.